



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 162]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934

No. 162]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

(निर्णायक समीक्षा)

विषय:- सऊदी अरैबिया और रूस मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित "हेक्सामाइन" के आयातों के संबद्ध में आरोपित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा ।

सं. 15/1000/2012-डीजीएडी.—यतः, समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथा-संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सऊदी अरैबिया और रूस (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) से आयातों के पाटन के संबंध में जाँच मूलरूप से 20 फरवरी, 2001 को शुरू की थी । मूल जाँच के अंतिम निष्कर्ष 15 फरवरी, 2002 की अधिसूचना सं. 12/1/2000-डीजीएडी के तहत जारी किए गए थे । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन बने रहने या उसकी सम्भावना और घरेलू उद्योग को क्षति की जाँच करने के लिए प्रथम निर्णायक समीक्षा जाँच 15 जून, 2006 को शुरू की थी । प्राधिकारी ने 14 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 08/1/2001(एसएसआर)-डीजीएडी के तहत अंतिम निष्कर्ष जारी किए थे और पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा में वृद्धि करने की सिफारिश की थी । संबद्ध देशों से हेक्सामाइन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की संवर्धित प्रमात्रा अधिरोपित करते हुए दिनांक 25 जुलाई, 2007 को अधिसूचना सं. 89/2007-सीमाशुल्क जारी की थी ।

2. यतः, सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, यदि उनका पहले से प्रतिसंहरण नहीं किया गया तो, का प्रभाव इस

अधिशोषण की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगा और उपर्युक्त नियम प्राधिकारी से पाटनरोधी शुल्क की अवधि बढ़ाने की जरूरत की समीक्षा करने की अपेक्षा करते हैं और प्राप्त जानकारी के आधार पर, यदि यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसे शुल्क का विस्तार करने के लिए पर्याप्त औचित्य है तो प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार से इसका विस्तार करने की सिफारिश कर सकते हैं। उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप मै0 सिमालिन कैमिकल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, बड़ोदरा और मै0 कानोरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, अंकलेश्वर ("आवेदक/याचिकाकर्ता") ने संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की निरंतरता अथवा पुनरावृत्ति होने और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति होने का आरोप लगाते हुए संयुक्त रूप से पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत विधिवत प्रमाणीकृत एक आवेदन दायर किया है और संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अधिशोषण पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसकी निरंतरता बनाए रखने और उसमें वृद्धि करने का अनुरोध किया है। यह याचिका, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म में और ढंग से की गई है तथा इसमें संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रथमदृष्टया साक्ष्य मौजूद है।

घरेलू उद्योग

3. यह आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से मै0 सिमालिन कैमिकल इण्डस्ट्रीज प्रा0लि0, बड़ोदरा और मै0 कानोरिया कैमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, अंकलेश्वर ("आवेदक/याचिकाकर्ता") द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदकों का संबद्ध वस्तु का भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा बनता है और इसलिए नियमों के आशय के अंतर्गत वे घरेलू उद्योग बनते हैं।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. मूल जाँच और प्रथम निर्णायक समीक्षा में अंतर्ग्रस्त उत्पाद हेक्सा मिथायलीन टेट्रामाइन था, जिसे हेक्सामाइन के रूप से भी जाना जाता है। चूँकि यह एक निर्णायक समीक्षा है इसलिए इस जाँच में वे सभी उत्पाद शामिल होंगे जो मूल जाँच और विगत निर्णायक समीक्षा जाँच में शामिल किए गए थे। प्रस्तावित जाँच में विचाराधीन उत्पादों का दायरा वही रहेगा जो इससे पहले अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों में विचाराधीन उत्पादों का दायरा रहा था। मूल जाँच में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत निम्नवत विचार किया है "वर्तमान जाँच में अंतर्ग्रस्त उत्पाद हेक्सा मिथायलीन टेट्रामाइन है जिसे बाजार में सामान्यतः हेक्सामाइन के रूप में जाना जाता है। हेक्सा मिथायलीन टेट्रामाइन एक सफेद रंग का क्रिस्टलीन पाँवडर होता है जिसका सुखद धात्विक स्वाद होता है। शुद्ध रूप में यह रंगहीन और गंधहीन होता है। इसका क्रिस्टलीकरण रासायनिक डोडेकेहेड्रान्स में होता है। हेक्सा मिथायलीन टेट्रामाइन यौगिक को एम्मोफार्म, मिथेनामाइन, सिस्टामीन, सिस्टोजेन, यूरोट्रोपीन के रूप में भी जाना जाता है।" इसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2921.29 और आईटीसी सं. 2921.2902 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल संकेतक है और यह इस जाँच के दायरे में किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

5. साक्ष्यों सहित विधिवत दायर आवेदन के मदेनजर और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार प्राधिकारी संबद्ध वस्तु के संबंध में प्रभावी शुल्क के अधिरोपण की निरंतरता बनाए रखने की जरूरत की समीक्षा करने और यह जाँच करने के लिए कि क्या इस शुल्क के समापन से पाटन की अवस्थिति बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, एतद्वारा निर्णायक समीक्षा जाँच प्रारम्भ करते हैं।

शामिल देश

6. इस जाँच में शामिल देश सऊदी अरबिया और रूस हैं।

जाँच अवधि

7. आवेदकों ने जाँच अवधि के रूप में जनवरी, 2011 से दिसम्बर, 2011 का प्रस्ताव किया है। केवल जाँच शुरुआत करने के उद्देश्य के लिए इस अवधि को जाँच अवधि के रूप में स्वीकार करते समय प्राधिकारी ने वर्तमान के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 पर विचार किया है। तथापि क्षति विश्लेषण में अप्रैल, 2008 से मार्च 2009, अप्रैल 2009 से मार्च 2010, अप्रैल 2010 से मार्च 2011 और जाँचावधि अर्थात् अप्रैल, 2011 से मार्च, 2012 की अवधि शामिल होगी। भौतिक क्षति की चुनौती के लिए जाँच की अवधि के पश्चात के आंकड़ों का परीक्षण भी किया जा सकता है।

प्रक्रिया

8. यह जाँच, यह निश्चित करेगी कि क्या उपाय के समापन से पाटन एवं क्षति की अवस्थिति बनी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी। इस समीक्षा में दिनांक 14 जून, 2007 की अधिसूचना सं. 8/1/2001-(एसएसआर)-डीजीलएडी (एसएसआर जाँच अंतिम निष्कर्ष) के सभी पहलू शामिल होंगे।

सूचना प्रस्तुत करना

9. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए, भारत में इस उत्पाद से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं को निर्धारित स्वरूप और ढंग से संगत जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचारों से अधोलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से पत्र भेजा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली-110107

10. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस अधिसूचना में दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित ढंग से जाँच से संगत निवेदन कर सकता है।

समय-सीमा

11. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई हेतु किया गया कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए ताकि यह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) से अधिक समय के भीतर पहुंच जाए। यदि निर्धारित समयावधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

12. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत मामले में अपने हित (हित की प्रवृत्ति सहित) के बारे में सूचित करें और अपनी-अपनी प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा नहीं जारी रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियाँ इस जाँच के शुरू होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

13. सभी हितबद्ध पक्षकार पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(1) के अनुसार प्रदत्त गोपनीय सूचना के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार एक गोपनीय तथा अगोपनीय सार प्रदान करेंगे। गोपनीय जानकारी का अगोपनीय पाठ या अगोपनीय सार पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे कि यह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जानकारी की सार्थक समझ प्रदान करा सके। यदि जानकारी उपलब्ध कराने वाले पक्षकार के विचार से ऐसी जानकारी इस तरह की है कि उसका भाव, सार में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो उसके कारणों का विवरण देना अपेक्षित होगा। बिना चिन्ह के उपलब्ध कराई गई सूचना अगोपनीय मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी किसी भी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

14. उपर्युक्त पैरा में किसी बात के उल्लिखित होने के बावजूद यदि प्राधिकारी इस तथ्य से संतुष्ट हो जाते हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या इसका सामान्यीकृत या सार रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उचित अवधि के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है अथवा जाँच में बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

(Sunset Review)

Subject: Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of 'Hexamine' originating in or exported from Saudi Arabia and Russia.

No. 15/1000/2012-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (herein after referred to as the AD Rules). Designated Authority had originally initiated investigations on dumping of imports from Saudi Arabia and Russia (hereinafter referred to as subject countries) on 20th February 2001. The final findings of the original investigations were issued on 15th February, 2002 vide notification no 12/1/2000- DGAD. The Designated Authority initiated first sunset review investigations to examine the continuation or likelihood of dumping and injury to the domestic industry on 15th June, 2006. The Authority issued Final Findings vide notification No. 08/1/2001 (SSR)-DGAD on 14th June 2007 and recommended enhancement in the quantum of anti dumping duty. Notification No. 89/2007-Customs was issued on 25th July, 2007 imposing the enhanced quantum of anti dumping duty on imports of Hexamine from the subject countries.

2. WHEREAS in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995 the antidumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Rules supra require the Authority to review the need for extension of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received that there is sufficient justification for extension of such duty, the Authority may recommend to the Central Government for its extension. In terms of the above Provision, M/s Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd., Vadodara and M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd., Ankleshwar ("The Applicant/Petitioner") have jointly filed a duly substantiated application

2615 G/12-2

alleging likelihood of continuance or recurrence of dumping of subject goods under anti-dumping rules and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties, imposed on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries. The petition is in the form and manner prescribed by the Authority and contains prima facie evidence for the continuation of anti-dumping duty on the subject goods from the subject countries.

Domestic industry:

3. The application has been jointly filed by M/s Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd., Vadodara and M/s Kanoria Chemicals & Industries Ltd., Ankleshwar on behalf of the domestic industry. As per the information available, the applicants account for a major proportion in Indian production of the subject goods and therefore constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.

Product under consideration and Like Article:

4. The product involved in the original investigation and first sunset review was Hexa Methylene Tetramine also known as 'Hexamine'. This being a Sunset review, therefore, the investigation covers the product covered in the original and previous sunset review investigations. The scope of the product under consideration in the proposed investigation shall remain the same as the scope of the product under consideration in the final findings earlier notified. In the original investigations, the Designated Authority has considered the scope of the product under consideration as follows: "The product involved in the present investigation is Hexa Methylene Tetramine known as Hexamine in market parlance. Hexa Methylene Tetramine is a white crystalline powder with a sweet metallic taste. In the pure form, it is colourless and odourless. It crystallizes in rhombic dodecahedrons. Hexa Methylene Tetramine compound is also known as Ammoform, Methenamine, Cystamine, Cystogen, Urotropine". It is classified under custom sub- heading 2921.29 of the Customs Tariff Act, 1975 and ITC No.2921.2901. The customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Initiation of Sunset Review:

5. In view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules, the Authority hereby initiates a Sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Country involved:

6. The countries involved in this investigation are Saudi Arabia and Russia.

Period of Investigation:

7. The applicants have proposed January 2011 to December 2011 as period of investigation. While adopting this period as POI only for the purpose of initiation, the Authority has considered April 2011 to March 2012 as the POI for the purpose of present

investigation. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2008-March 2009, April 2009-March 2010, April 2010-March 2011 and the Period of Investigation (POI) viz. April 2011 to March 2012. For threat of material injury, the data beyond the POI may also be examined.

Procedure:

8. The investigation will determine whether the expiry of the measure would likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. The review covers all aspects of Notification No. 08/1/2001 (SSR)-DGAD on 14th June 2007 (final findings of the SSR investigation).

Submission of Information:

9. The known exporters in the subject country, the government of the subject country through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**The Designated Authority,
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.**

10. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit stated in this Notification.

Time Limit:

11. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

12. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis:

13. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7(2) of the AD Rules for the confidential information provided as per Rule 7(1) of the AD Rules. The non-confidential version or non-confidential summary of the confidential information should be in sufficient detail to provide a meaningful understanding of the information to the other interested parties. If in the opinion of the party providing

information, such information is not susceptible to summary; a statement of reasons thereof is required to be provided. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information.

14. Notwithstanding anything contained in Para above, if the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

Inspection of public file:

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation:

16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority